विवरण III

मिनी मिशन के अन्तर्गत प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

राज्य	परियोजना का नाम	प्राक्कलित लागत	अभियुक्ति
1	2	3	4
1. अरूणाचल प्रदेश	21,300 लोगों के लिये 19 हैंड-पम्पों वाली और 70 पाइप द्वारा जल सप्लाई की दो प्रकार की 13 योजनाओं के लिए पूर्वी सियांग मिनी मिशन जिले की गतिविधियों का समेकन	26.101	विचाराधीन है ।
2. असम	8.26 लाख लोगों के लाभ के लिए 207 गांवों में 206 योजनाओं के लिये कच्छार मिनी मिशन जिले में चल रहे कार्यों का समेकन	85.84	मिनी मिशन के अन्तर्गत 44.167 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे और 32.271 लाख रुपये अन्य स्रोतों से जुटाये जायेंगे ।
3. गुजरात	डांग में मिनी मिशन परियोजनाएं	23.06	अनुमोदित
4. हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा जिले में मिनी मिशन परियोजनाएं	87.83	अनुमोदित ।
5. जम्मू व कश्मीर	उधमपुर जिले में मिनी मिशन परियोजना	94.03	अनुमोदित निधियां रिलीज कर दी गई
	अनन्तनाग जिले में मिनी मिशन परियोजना	92.66	–वही–
6. कर्नाटक	रायचूर में मिनी मिशन परियोजना	77.51	अनुमोदित
7. मध्य प्रदेश	राजगढ़ जिले में मिनी मिशन परियोजना	74.61	–वही–
	शाहडोल में मिनी मिशन परियोजना	58.70	–वही–
8. राजस्थान	चुरू मिनी मिशन परियोजना हेतु संशोधित परियोजना (तीन योजनाएं) संशोधित लागत (1169.00 करोड़ रु०)	531.71	विचाराधीन (372 लाख रु० की अतिरिक्त लागत हेतु अनुरोध
9. त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा मिनी मिशन जिले में चल रही गतिविधियों का समेकन	430.44	अनुमोदित की गई 85.58 लाख रू० की राशि प्रौद्योगिक मिशन की निधियों में से और 1944.45 लाख रुपये त्वरित ग्रामीण पेयजल सप्लाई कार्यक्रम से पूरी की जाएगी ।
	कुल योग	1582.491	

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिमान के आधार पर भारत में कृषि उत्पादों के लिए बाजार

1502. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादन जिसमें एक बिन्दु कर प्रणाली रहे, के व्यापार के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिमान के आधार पर भारत में एक बाजार की स्थापना करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Proposals from the voluntary organisations for development of Wasteland

1503. SHRI GOPALSINGH G. SOLANKI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether 48 percent of the national land area is degraded wasteland ;

(b) whether Government have received any proposals from the voluntary organisations for development of wasteland ;

(c) if so, the details thereof and the steps taken to implement these proposals, State-wise ;

(d) the names of voluntary organisations which are engaged in development of wasteland, State-wise ; and

(e) the effective measures taken by Government to reverse the degradation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT OF WASTELANDS. DEVELOPMENT) (COL. RAO RAM SINGH) : (a) No detailed survey has yet been conducted for the identification of wastelands, but according to one estimate out of the country's landmass of 329.00 million hectares, 129.53 million hectares is wastelands. Thus as a percentage of the total land mass in the country wastelands are 39%.

(b) to (d) Government has been receiving location specific proposals for development of wastelands by voluntary organisations which, if conforming to the guidelines, are approved for financial assistance under the Grant-in-Aid Scheme. In addition Voluntary Organisations can also submit proposals for funding under Integrated Wasteland Development Projects scheme. The state wise list of the Voluntary Agencies provided assistance under Grant-in Aid scheme and Integrated Wasteland Development Projects scheme is at Statement-I and II respectively (*See* below).

(e) Under point No 16. of the 20 Point Programme development of wastelands is taken up under the various afforestation/ tree plantation and related activities under the Central and State plans. Physical targets which are fixed from year to year depend upon availability of funds. The targets for 1993-94 under point 16 of the 20 point programme is development of 11.79 lakh hectares of land including wastelands.

Statement I

State-wise list of Voluntary Organisations provided assistance under Grant-in-aid Scheme by the reconstituted National Wastelands Development Board from September 1992 *to* 23-02-94

ANDHRA PRADESH:

1. Socio-Economic Educational Development Society
2. Praja Bhartiya Seva Samiti
3. Rural Education & Economic Development Society
4. Krishnaveni Tree Grower's Society
5. Integrated Rural Development Welfare Society
6. Sawajanya Youth Association
7. Rural Development Society
8. Social Action Social Development
9. Venkateshwer Tree Grower's Cooperative Society
10. Rishi Valley School
11. People's Organisation for Rural Poor